विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0 588/2019 हेम सिंह योग, सोशल वर्कर पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 07.12..2019 को अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) (जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के प्रतिनिधि), संयुक्त नगर आयुक्त (नगर आयुक्त नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन के प्रतिनिधि) एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा किया गया। जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के आदेशानुपालन में उक्त इकाई का पुनः निरीक्षण दिनांक 09.12.19 को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा की अध्यक्षता में नगर आयुक्त नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सैग्रीग्रेशन, ट्रीटमेन्ट एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट को संचालित करने वाली संस्था मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा के प्रतिनिधि के रूप में श्री एम0के0 गर्ग, प्रबन्ध निदेशक उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।

1. नगर पलिका परिषद जो कि वर्तमान में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के मथुरा जोन क्षेत्र से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ठ निस्तारण हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल (निकट एस0टी0पी0, बल्देव रोड, तहसील व जनपद–मथुरा) पर लैण्डफिल साइट एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट की स्थापना हेतु जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के मींटिंग हाल में दिनांक 11.11.2008 को अपरान्ह 02 बजे लोक सुनवायी सम्पन्न हुई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति लोक सुनावाई की कार्यवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्था सिया (SEIAA) ने अपने सन्दर्भ संख्या 438/SEAC/208/2008 दिनांक 20. 03.2009 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के लैण्डफिल व बायो कम्पोंस्टिंग प्लांट हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी (प्रति संलग्न–सलग्नक 01)। पर्यावरणीय स्वीकृती प्राप्त करने के पश्चात् मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट से बायो कम्पोस्टिंग तैयार करने के उददे्श्य से संयन्त्र की स्थापनार्थ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि कोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 08.08.2012 को बोर्ड में आवेदन किया गया जिसके परीक्षणोरोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एफ 21528/सी–4/एन0ओ0सी0–675/13 दिनांक 03.04.2013 द्वारा सशर्त आनापत्ति निर्गत किया गया (प्रति संलग्न–सलग्नक 02)। कार्यालय अभिलेखानुसार प्लांट की क्षमता 185 मी0टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट कर बायों कम्पोस्टिंग तैयार किया जाना है। सस्था द्वारा प्लांट के संचालनार्थ अर्थात सहमति जल/वायु हेतु वर्तमान में आवेदन नहीं किया गया है। तथा पूर्व में निर्गत एन0ओ0सी में निहित शर्तो का अनुपालन न होने के कारण बोर्ड में जमा रू0 दस लाख की बैंक गारन्टी बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 12.03.2015 द्वारा जप्त की जा चुकी है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया की साईट पर लगभग 1.5 लाख मी0टन नगरीय अपशिष्ट भण्डारित है जिसके शुद्धिकरण/निस्तारण हेतु विस्तृत परियोजना आख्या(डी0पी0आर0) बनाकर वृत्तीय स्वीकृती हेतु नगर निगम द्वारा दिनांक 18.09.2018 को

उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा चुकी है (प्रति संलग्न–सलग्नक 03)। निरीक्षण के दौरान शिकायतीकर्ता के रूप में श्री हेम सिंह उपस्थित थे। उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व से भण्डारित नगरीय ठोस अपशिष्ठ में समय–समय पर आग लग जाने से वायु प्रदूषण एवं दुर्गन्ध की समस्या बनी रहती है। निरीक्षण के समय क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सैग्रीग्रेशन एवं बायो कम्पोस्टिंग का प्लांट संचालित पाया गया किन्तु परिसर के अन्दर अत्यधिक मात्रा में दुर्गन्ध व्याप्त था। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पूर्व में निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट के ढ़ेर में आग लगने एवं वायु प्रदूषण की शिकायतें उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रायः मिलती रहती है अतः ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। बायो कम्पोसिटिग के दौरान प्रक्रिया उर्त्सजन से वायु प्रदूषण की समस्या महसूस की गयी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के प्रतिनिधि एवं मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा के प्रतिनिधि को वैज्ञानिक विधि से बायो कम्पोस्टिंग प्लांट का संचालन एवं परिसर के अन्दर हाउस कीपिंग में सुधार हेतु निर्देशित किया गया।

2. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के प्रतिनिधि श्री ए0के0 सिंह, सहा0 नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं बायो कम्पोस्टिंग हेतु मै0 मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा से अनुबन्ध किया गया है। पूर्व से भण्डारित नगरीय ठोस अपशिष्ठ जिसकी मात्रा लगभग–1.5 लाख मी0टन है के उपचार एवं निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 बनाकर उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रेंषित की जा चुकी है जो कि शासन में लम्बित है।

3. समिति द्वारा प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्माणाधीन उद्योग मै0 पैर्टसन इनर्जी प्र0 लि0 ग्राम– शहजाद पुर, ट्रान्स यमुना, लक्ष्मी नगर, मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री के0वेंकटेश, प्रेसिंडेन्ट उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में परीक्षण उत्पादन आगामी सप्ताह में आरम्भ कर दिया जायेगा। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उद्योग की स्थापनार्थ टी0टी0जेड़ प्राधिकरण आगरा के पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा अनुमति प्राप्त है तथा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्र सं–1335/एन0ओ0सी0–1109/17 दिनांक 20.12.2017 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है(प्रति संलग्न–सलग्नक 04)। । निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है कि उद्योग में परीक्षण उत्पादन से पूर्व बोर्ड से नियमानुसार सहमति जल/वायु प्राप्त कर ली जाये। उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) का अनुपालन किये जाने हेतु दिनांक 09.12.2019 को नोटिस प्रेषित किया गया।

4. नगरीय ठोस अपशिष्ठ के बायो कम्पोस्टिंग के दौरान जनित होने वाले लीचेड इफ्लूएन्ट के शुद्धिकरण की व्यवस्था स्थापित नहीं है जिसके रिसाव से भूमिगत प्रदूषण होने की सम्भावना है। निरीक्षण के समय उपस्थित मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा के प्रतिनिधि को लीचेड

2.....

इफ्लूएन्ट के उपचार एवं निस्तारण व्यवस्था शीघ्र स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 09.12.19 को निरीक्षण के समय मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा के प्रतिनिधि को नगरीय ठोस अपशिष्ठ के उठान हेतु वाहनों को ढक कर डम्पिंग ग्राउण्ड तक ले जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा यथा सम्भव सी0एन0जी0 चालित वाहनों का प्रयोग किया जाये जिससे वाहनों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

5. निरीक्षण के समय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह योगाचार्य द्वारा दिये गये शिकायती पत्र दिनांक 01.05.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में नगर निगम को ए0टी0आर0 के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या एवं निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटो की फोटोग्राफ की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा

9.12.19

(ए0के0 सिंह)
संयुक्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

09.12.19

(बृजेश कुमार),
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मथुरा।

9/12/19

(रवीन्द्र कुमार मांदड़)
नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

9/12/19

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी महोदय
मथुरा।

सलग्नक - (1)

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-
Phone: 91-522-2300541, Fax: 91-522-23
E-mail: up.seiaa@yahoo.com

Ref. No. 438 /SEAC/208/2008 Date 20.3. 2009

To,

Shri V.P. Singh,
General Manager,
Construction and Design Services,
U.P. Jal Nigam, 2, Lal Bahadur Shashtri Marg,
Lucknow-226001.

Sub.: Regarding Environmental Clearance for Solid Waste Management Scheme in Mathura.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 227/G-2-07/26 dated 24/05/2008 addressed to the Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority, UP and letter no. 304/G-2-10/01 dated 30-06-08 addressed to the Director, Directorate of Environment on the subject as above. The State Level Expert Committee has considered your application and has been given to understand that:

(1) The Environmental clearance is sought for development of sanitary land fill and composting at near S.T.P, Baldev Road, Tehsil Mathura, District-Mathura.
(2) The proposed project is spread over an area of 27 acres.
(3) The proposed compost plant will be designed to process 100 TPD of Municipal Solid Wastes
(4) During the presentation the project proponent made a detailed presentation on the Environmental Impact of the project, response to the Additional Terms of References provided to the project proponent, compliance to the Municipal Solid Waste Handling Rules, 2000 and the Environment Management Plan.
(5) All the recommendations made in the Environment Impact Assessment Report must necessarily be implemented and the project should comply fully with the Municipal Solid Waste Handling Rules, 2000.

Based on the recommendations of the State Level Expert Committee the State Level Environment Impact Assessment Authority has decided to grant the Environmental Clearance to the project to the effective implementation of the following conditions:

a. **General Conditions:**

1. It should be clearly specified that the project proponent would ensure that all the standards related to ambient air quality and emission/effluent standards as prescribed by MoEf are strictly complied with.
2. The project proponent will have to ensure that they obtain No Objection certificate from the U.P. Pollution Control Board before start of construction.
3. The proposed land use should be in accordance to the prescribed land use.
4. Proper operation & maintenance of the project shall be ensured after construction phase. Conditions and guidelines for operation and penalties for non-compliance should be specifically prescribed.

5. Information with respect to this clearance & other related documents shall be communicated by the project proponents to the concerned agencies (other than SEIAA and SEAC) as prescribed in the EIA notification No. SO 1533(E) dated 14/09/2006.
6. In addition to the proposed compensatory plantation (3 Trees planted for every tree cut) it shall be ensured that 33% of total lands in the project areas are planted with shade giving and ecologically friendly trees.
7. A specific waste collection and transportation system should be ensured for conveying the waste scientifically and in a safe manner to the proposed MSW landfill site.
8. Leachate should be collected and disposed in a manner such that it may not contaminate the ground water.
9. The general conditions attached to the list of the proposed activities requiring environmental clearance as given in gazette notification dated 14/09/06 issued by Govt. of India and which read as follows should be strictly complied with -" Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries." Should not be violated." In case of any violation clearance shall be obtained from The Government of India, as prescribed.
10. The standards regarding ground water, ambient air, leachate quality and compost quality shall be duly followed as per Municipal Solid Wastes (M&H) Rules, 2000.
11. A comprehensive EIA shall be undertaken and the environment management plan and detailed project report (DPR) revised accordingly also taking into view the conditions stipulated in this clearance. This report shall be submitted to this authority by March, 2010, failing which this clearance will automatically be cancelled. The comprehensive EIA should address to all the issues raised in the public hearing held on 11/12/2008 to which project proponent were a party. The DPR and the EMP should be suitably revised to incorporate and mitigate the observations/objections made in the public hearing also.
12. The project proponents will set up a separate environmental management cell for effective implementation of the EMP etc. as well as stipulated environmental safeguards under the supervision of a senior experienced executive.
13. A three monthly monitoring report should be submitted to the Authority regarding the implementation of the stipulated conditions.
14. The EIA Authority may stipulate any other conditions or environmental safeguards subsequently, if deemed necessary, which should be complied with.
15. The Authority reserves the right to revoke this clearance if any of the conditions stipulated are not complied with the satisfaction of Authority.
16. Full support should be extended to concerned officers/authorities by the project proponents during their inspection of the project for monitoring purposes by furnishing full details and action plan including action taken reports in respect of mitigative measures and other Environmental protection activities.
17. In the event of a change in project profile or change in the implementation agency, a fresh reference should be made to the Authority prior to change.
18. Regular noise levels should be monitored during construction and operation phase.
19. Specifications regarding selection of landfill site, facilities at the site, specifications for land filling, pollution prevention, water quality monitoring, ambient air quality monitoring, plantation at land fill site, closure of landfill site and post care, leachate treatment and disposal should be strictly in compliance to the provisions of the Municipal Solid Wastes (M&H) Rules, 2000.A report in this regards should be prepared and submitted to the Authority within 3 months.

b. <u>Specific Conditions:</u>

1. As the proximity to the cultural monuments regarded as a sensitive issue, the landfill site should be developed at a safe distance from their boundaries. Landfill site should also be situated at safe distance from human settlements and that a no entry zone be created so that general public does not enter into the area.
2. Boilers will not be used.
3. Green belt should be developed in 33% of the total project area.

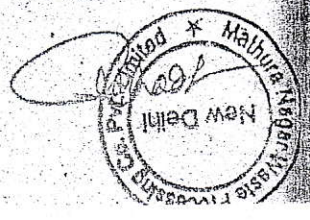

4. Suitable conditions for odour control should be imposed. Herbals sanitizer and composting enzymes will be used to minimize odour.
5. All the street lighting should be solar and that CFLs should be used.
6. For the leachate treatment, it has been proposed that mechanical aeration leachate treatment will be followed. Necessary conditions for the sewage treatment should also be imposed.
7. The project proponent will duly follow post clearance monitoring as per Municipal Solid Waste Rules, 2000.
8. The following points may also be considered while making the comprehensive EIA report and this report should be submitted by March, 2010.
9. Wind speed and direction changes with time and space depending on the topography and seasons. Wind rose should, therefore be made for each month separately for each sampling site. There should be at least 2 sites in the down wind prominent direction.
10. CO measurement should be made by NDIR and eight hourly average with 98 percentile should be given.
11. Methods used for analysis should be specifically provide.
12. 98 percentile values should be taken into consideration for comparison with standards.
13. Impact of project on quality of life should be given.
14. Leq should be determined from 24 hours days-night data at each site twice a week.

The Authority felt that necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and that if this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled. It should also be insured that approved plans and proposals as per provisions of para-3 of appendix-5 of the notification No.S.O. 1533 dated 14/09/2006 are submitted with 03 months of the receipt of this letter failing which the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA notification, 2006 including amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.09.06 issue by Govt. of India.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary,
SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Administrative Officer, Directorate of Environment for Monitoring and Web Updation.

(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC

Mathura Nagar Nigam

संलग्नक - (2)

प्राप्त
08/04/13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F21828 / सी-4/NOC-675/13 दिनॉक 3-4-13

सेवा में,

मैसर्स मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी,
नगला–कोल्ह रोड, लक्ष्मी नगर,
यमुना पार, तहसील–महावन,
मथुरा

21
NOC 735
09/04/13

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से पूर्व से कम प्रदूषण भार संबंधी उत्पाद परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन। जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के अन्तर्गत उद्योग स्थापना से पूर्व सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–[illegible] को प्राप्त है, का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि [illegible] को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामन्य शर्तों (संलग्नक) के [illegible] के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

१ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों [illegible] है [illegible] जा रहा है –

(क) [illegible]

[illegible]

(ख) [illegible]

(ग) मुख्य कच्चे माल : [illegible] 185 टन / दिन।

....

....

(ङ.) **प्रयुक्त ईधन** : नैचुरल गैस मात्र।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

२. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

३. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

४. घरेलू उत्प्रवाह, सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

५. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में एक माह में अवश्य प्रस्तुत की जाये।

६. उद्योग में नेचुरल गैस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ईधन का प्रयोग नही किया जाये। यद्यपि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में किसी भी नये प्रदूषणकारी श्रोत की स्थापना प्रतिबंधित है। संचालन से पूर्व भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

७. उद्योग पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर राज्य बोर्ड को प्रेषित करे।

८. उद्योग से देय जल, वायु सहमति शुल्क सहित जल उपकर का भुगतान किया जाये।

९. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संचालन से आस पास के क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव/कुप्रभाव न पड़े।

१०. नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था का निर्माण कार्य वहाँ के प्रथम सतही भू–जल स्तर से कम से कम दो मीटर ऊँची रखी जाये। जिससे लीचेट आदि उत्प्रवाह के कारण भूजल प्रदूषित न हो पाये।

११. नगरीय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त कर ही संचालन किया जाये।

१२. लोक सुनवायी दिनॉक–११.११.२००८ में इंगित बिन्दुओं व पर्यावरणीय स्वीकृति में इंगित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये व प्रत्येक माह सत्यापित सूचना बोर्ड को प्रेषित की जाये। लीचेट व फर्श एवम् संयंत्र वासिंग उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर पुनः प्रयोग में लाया जाये। इस हेतु पूर्ण विवरण १५ दिन में जमा करें।

१३. ट्रायल सहमति प्राप्त कर ही संचालन किया जाये।

१४. उद्योग परिसर के कम से कम ३३ प्रतिशत क्षेत्रफल में उ०प्र०शासन के पत्र दिनॉक–२२.०२.२००५ के अनुपालन में हरित पट्टिका व वृक्षारोपण किया जाये।

15. जल निगम, नगर पालिका परिषद व कम्पनी के बीच हुए समझौतों का पालन किया जाये। एग्रीमेन्ट के क्लाज 6.15 के अनुसार कम्पनी को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन का दायित्व चिन्हित है। अतः टी०टी०जेड अथॉरिटी से भी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रेषित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में **एक माह** तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :

१. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा।

२. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

3.4.13

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
सर्किल–४

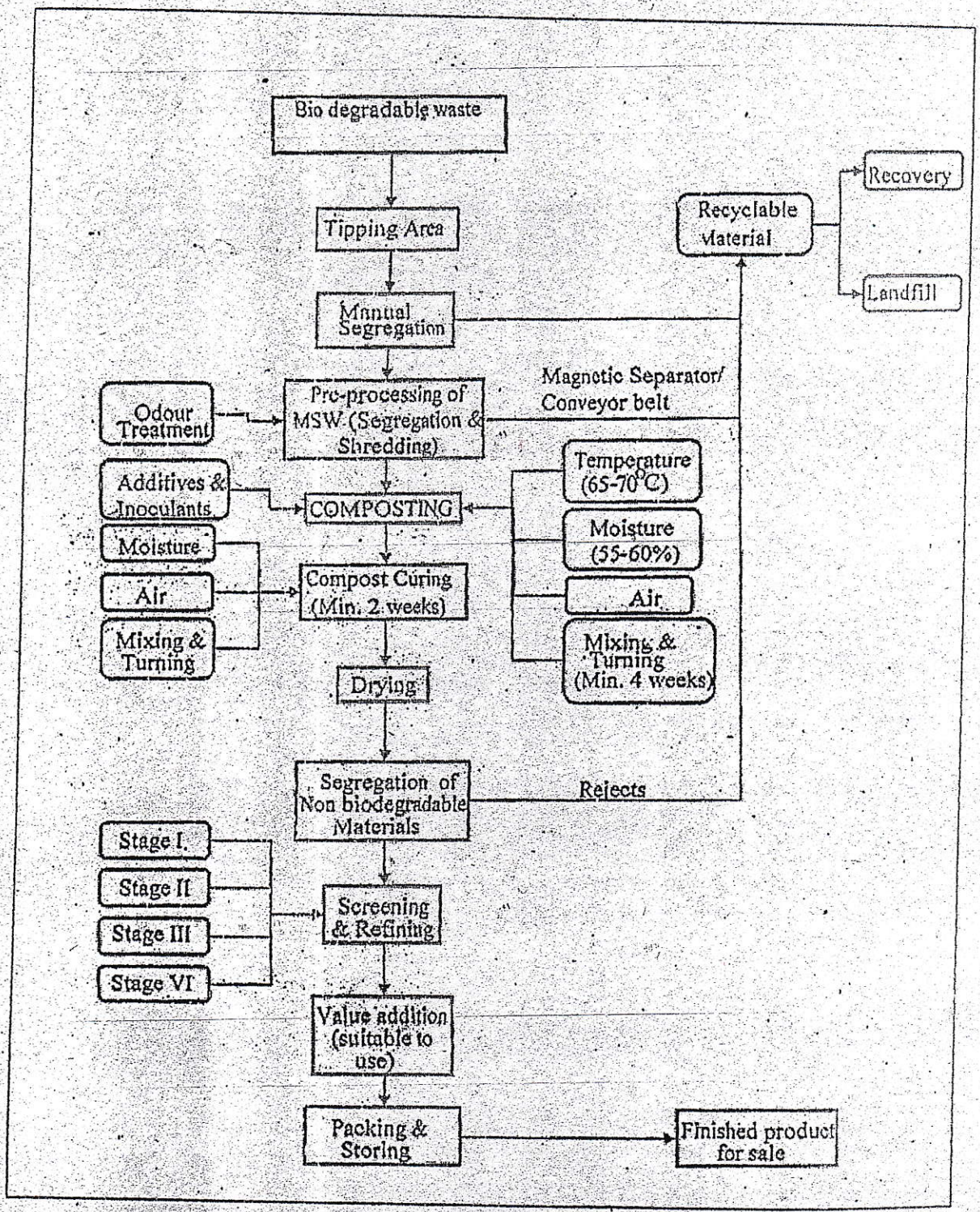

Figure E-1 Process Design for MSW Compost

MWP

MATHURA NAGAR WASTE PROCESSING COMPANY LTD.

Date: 2nd July, 2015

Ref: MWP/15-16/472

To,

Dr. A.K. Gupta,
Scientist-C, Regional Office (Central Region)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H'
Aliganj, Lucknow-116024
Fax: 05222326696, 2324025

Subject: Environmental Clearance for Solid Waste Management Scheme in Mathura

Dear Sir,

This letter is in reference of your letter no. VII/Env/SCL-UP/137/2015/324 dated 12.6.2015 and Letter from Mr. A.K. Rai 442/M.Pr. Ni-8/G 8-10/02 dated 26.6.2015 regarding above cited project. It was stated in above referred letter that Concessionaire i.e. MNWPCL shall be submitting the compliance report.

We would like to submit that we have terminated the project vide our letter MNWPCL/2013-14/06-02/441 dated 07.06.2014 but during our pre termination period, we were maintaining and complying all the Specific and General Conditions as stated in the EC letter issued by MoEF vide letter 438/SEAC/208/2008 dated 20.3.2009.

Hence, as the said project has been terminated by MNWPCL so compliance Report and other statuary compliance are to be complied by the competent Authority or Mathura Nagar Palika Parishad.

Thanking You.

Yours Faithfully,

Authorized Signatory
Mathura Nagar Waste Processing Company Limited

CC:

1. Executive office, Nagar Palika Parishad, Mathura
2. Project manager, Unit-17, C&DS, UPJN, Mathura

04-07-15

Mathura Nagar Waste Processing Company Ltd.
Nagla Kolhu Road, Laxmi Nagar, Yamuna par, Mathura 281001

SPML Engineering Life

A PPP between SPML & Mathura Nagar Palika Pari

Scanned by CamScanner

अनुस्मारक

एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या: 281 /न०आ०का०/न०नि०म०वृ०-मथुरा/2019-20

दिनांक: 05-12-19

सेवा में,

सचिव
उ0प्र0 शासन
नगर विकास विभाग
लखनऊ।

विषय– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0–1130 दिनांक 18.09.2018, 1220 दिनांक 17.10.2018, 1562 दिनांक 12.02.2019, 28 दिनांक 16.04.2019, 235 दिनांक 25.05.2019 एवं 538 दिनांक 29/07/2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के नगला कोल्हू स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु अवगत कराया गया है ।

अवगत कराना है कि, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012 में प्लान्ट का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी0एंडडी0एस0 शाखा उ0प्र0 जलनिगम मथुरा के द्वारा पूर्ण कराया गया । प्लांट निर्माण से पूर्व नगर पालिका परिषद, मथुरा द्वारा प्लांट के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की गयी, तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा वर्ष 2013 में प्लांट प्रबन्धन एवं संचालन हेतु मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कं0 लि0, मथुरा को हस्तांतरित कर दिया गया । माह जून 2014 में उक्त संस्था द्वारा प्लांट का संचालन कार्य बन्द कर आर्बिटेशन का बाद दायर करदिया गया, जिसका प्रकरण मा. उच्च न्यायालय में लम्बित है । वर्ष 2014 से नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा अपशिष्ट उक्त प्लांट पर ही एकत्रित किया जाता रहा, जिस कारण उक्त स्थान पर काफी अधिक मात्रा में अपशिष्ट एकत्रित हो गया। नगर निगम द्वारा उक्त प्लांट मार्च 2019 में एस0वी0एम0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 को संचालन एवं प्रबन्धन हेतु हस्तांतरित किया गया है । प्लांट पर अत्यधिक मात्रा में कचरा एकत्रित हो जाने के कारण प्लान्ट का अधिकांश भाग कचरे से घिरा हुआ है, जिस कारण प्लांट संचालन कार्य बाधित हो रहा है । प्लांट पर प्रतिदिन आने वाले कचरे के निस्तारण हेतु विन्ड्रोज कम्पोस्टिंग एंव आर0डी0एफ0 के लिए भी भूमि शेष नहीं हैं, जिस कारण कूड़े का निस्तारण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है ।

दिनांक 04.07.2019 को श्री डी0पी0 सिंह जी, अध्यक्ष, उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कमेटी के द्वारा मथुरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया है, भ्रमण के दौरान मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्लांट पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से एक माह के अन्दर कराने एवं प्लांट का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त एकत्रित कचरे (लीगेसी वेस्ट) (जिसकी मात्रा लगभग एक लाख टन है) का निस्तारण अविलम्ब किया जाना अति आवश्यक है, कृपया लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु उचित मार्गदर्शन करने का कष्ट करें ।

5/12/19

(रवीन्द्र कुमार माँदड)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 538 /न0आ0का0/ न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2019–20, दिनांक : 21/7/19

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 शासन
नगर विकास विभाग
लखनऊ।

विषय **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0–1130 दिनांक 18.09.2018, 1220 दिनांक 17.10.2018, 1562 दिनांक 12.02.2019, 28 दिनांक 16.04.2019 एवं 235 दिनांक 25.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के नगला कोल्हू स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु अवगत कराया गया है।

अवगत कराना है कि, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012 में प्लान्ट का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी0एंडडी0एस0 शाखा उ0प्र0 जलनिगम मथुरा के द्वारा पूर्ण कराया गया। प्लांट निर्माण से पूर्व नगर पालिका परिषद, मथुरा द्वारा प्लांट के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की गई, तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा वर्ष 2013 में प्लांट प्रबन्धन एवं संचालन हेतु मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कं0लि0, मथुरा को हस्तांतरित कर दिया गया। माह जून 2014 में उक्त संस्था द्वारा प्लांट का संचालन कार्य बन्द कर आर्बिटेशन का वाद दायर कर दिया गया, जिसका प्रकरण मा. उच्च न्यायालय में लम्बित है। वर्ष 2014 से नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा अपशिष्ट उक्त प्लांट पर ही एकत्रित किया जाता रहा, जिस कारण उक्त स्थान पर काफी अधिक मात्रा में अपशिष्ट एकत्रित हो गया। नगर निगम द्वारा उक्त प्लांट मार्च 2019 में एस0वी0एम0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 को संचालन एवं प्रबन्धन हेतु हस्तांतरित किया गया है। प्लान्ट पर अत्यधिक मात्रा में कचरा एकत्रित हो जाने के कारण प्लान्ट का अधिकांश भाग कचरे से घिरा हुआ है, जिस कारण प्लान्ट संचालन कार्य बाधित हो रहा है। प्लान्ट पर प्रतिदिन आने वाले कचरे के निस्तारण हेतु विन्ड्रोज कम्पोस्टिंग एवं आर0डी0एफ0 के लिए भी भूमि शेष नहीं है, जिस कारण कूडे का निस्तारण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है।

दिनांक 04.07.2019 को श्री डी0पी0 सिंह जी, अध्यक्ष, उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कमेटी के द्वारा मथुरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया है, भ्रमण के दौरान मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्लांट पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण वैज्ञानित तरीके से एक माह के अन्दर कराने एवं प्लांट का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त एकत्रित कचरे (लीगेसी वेस्ट) (जिसकी मात्रा लगभग एक लाख टन है) का निस्तारण अविलम्ब किया जाना अतिआवश्यक है, कृपया लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु उचित मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

20/7/19

(रवीन्द्र कुमार माँदड)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संकल्प सेवा समर्पण

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 235 /न0आ0/ न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2019–20 दिनांक : 25/05/2019

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 शासन,
नगर विकास विभाग
लखनऊ।

विषय **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित पत्र सं0– 234 / सं0न0आ0 / न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2019–20 दिनांक 09.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के नगला कोल्हू स्थित सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के प्रबन्धन एवं संचालन सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गई है। उपरोक्त पत्र में त्रुटिवश डी0पी0आर0 प्रेषित करने का उल्लेख किया गया है, जबकि नगला कोल्हू स्थित प्रोसेसिंग प्लान्ट पर विगत 4 वर्षो से संचालन बन्द रहने के कारण एकत्रित लगभग एक लाख टन कूडे के निस्तारण हेतु प्रारंभिक आगणक शासन को प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, मथुरा द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012 में प्लांट का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0 शाखा उ0प्र0 जलनिगम मथुरा के द्वारा पूर्ण कराया गया। प्लांट निर्माण से पूर्व नगर पालिका परिषद, मथुरा द्वारा प्लांट के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की गई है, तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा वर्ष 2013 में प्लांट प्रबन्धन एवं संचालन हेतु मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कं0लि0, मथुरा को हस्तांतरित कर दिया गया। माह सितम्बर 2014 में उक्त संस्था द्वारा प्लांट का संचालन कार्य बन्द कर आर्बिटेशन का वाद दायर कर दिया गया, जिसका प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। वर्ष 2014 से नगर पालिका द्वारा अपशिष्ट उक्त प्लांट पर ही एकत्रित किया जाता रहा, जिस कारण उक्त स्थान पर काफी अधिक मात्रा में अपशिष्ट एकत्रित हो गया। नगर निगम द्वारा उक्त प्लांट मार्च 2019 में एस0वी0एम0 इन्फ्रस्टेट प्रा0 लि0 को संचालन एवं प्रबन्धन हेतु हस्तांतरित किया गया है। प्लान्ट पर अत्यधिक मात्रा में कचरा एकत्रित हो जाने के कारण प्लांट का अधिकांश भाग कचरे से घिरा हुआ है, जिस कारण प्लांट संचालन कार्य बाधित हो रहा है।

अतः उक्त एकत्रित कचरे (Legacy Waste) का निस्तारण किया जाना अतिआवश्यक है, कृपया एकत्रित कचरे (Legacy Waste) के निस्तारण के लिए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन करने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

79

कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 28 /कै0का0न0आ0का0/न0नि0म0वृ0–मथुरा/2018–19, दिनांक: 16-04-19

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

सेवा में,

स्टेट मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
दीनदयाल उपाध्याय शोध एवं प्रशिक्षण,
संस्थान, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

विषयः नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट/लैण्ड रिक्लेम/बायोमांइनिंग के मद में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कृपया पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1130, दिनांक 18.09.2018, संख्या–1220, दिनांक 17.10.2018 व संख्या–1562, दिनांक 12.02.2019 का सन्दर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विस्तृत डी0पी0आर0 इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

यह अवगत कराना है कि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा क्षेत्र में नये ग्रामों के जुड़ जाने के कारण सम्प्रति नगला कोल्हू स्थित डम्पिंग साईट नगर के मध्य में आ गई है तथा इस साईट पर दबाव भी बढ़ गया है। इस स्थान पर पूर्व से जमा अपशिष्ट का निस्तारण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह साईट अब लगभग भर चुकी है तथा नई साईट के लिये मानव आबादी, जल स्त्रोत आदि से पर्याप्त दूरी पर स्थित बड़े भूखण्ड की उपलब्धता नहीं हैं। यह भी अवगत कराना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत पुराने अपशिष्ट का भी निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। जिसके कारण नगर निगम पर दबाव है। यदि यह साईट खाली हो जाती है, तो अगले कई वर्षो तक पुनः इसी साईट को प्रयोग में लाया जा सकेगा व नई भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि पूर्व में इस संबंध में प्रेषित किये गये पत्रों व डी0पी0आर के क्रम में शीघ्र मार्ग दर्शन करने व निर्णय लेने का कष्ट करें।

16/4/19

(समीर वर्मा)
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/4/19

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 1562 /न0आ0का0/न0नि0म0वृ0–मथुरा/2018–19 दिनांक : 12/2/19

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

सेवा में,

स्टेट मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
दीनदयाल उपाध्याय शोध एवं प्रशिक्षण,
संस्थान, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

विषयः नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट/लैण्ड रिक्लेम/बायोमाईनिंग के मद में धनराशि उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या 1130, दिनांक 18.09.2018 व पत्र संख्या 1220, दिनांक 17.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव के औचित्य का वर्णन करते हुये डी0पी0आर0 संलग्न कर प्रेषित की गई थी।

अनुरोध करना है कि इस विषय में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये है। जिसके कारण स्थानीय स्तर पर एकत्रित पुराने अपशिष्ठ का निस्तारण नहीं किया जा पा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कृपया तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(समीर वर्मा)
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

(77)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 1220 / न0आ0का0 / न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2018–19 दिनांक : 17/10/2018

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

सेवा में,

स्टेट मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
दीनदयाल उपाध्याय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

विषयः **नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट / लैण्ड रिक्लेम / बायोमाईनिंग के मद में धनराशि उपलब्ध कराने जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं 1130 / न0आ0का0 / न0नि0म0वृ0 मथुरा / 2018, दिनांक 18.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव के औचित्य का वर्णन करते हुये डी0पी0आर0 संलग्न कर प्रेषित की गई थी।

अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है। जिसके कारण महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। यह भी अनुरोध करना है कि यदि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में किसी अन्य सूचना की आवश्यकता हो तो उसके विषय मे निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे वॉछित तथ्य व सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

(समीर वर्मा) 17/10/18
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा वृन्दावन,
मथुरा

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ।

17/10/18
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा वृन्दावन
मथुरा

78

एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 1130 /न0आ0का0/न0नि0म0वृ0–मथुरा/2018–19 दिनांक: 18-09-2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन
नगर विकास अनुभाग–05
लखनऊ।

विषय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के मद में धनराशि उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

अनुरोध है कि नवसृजित नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अर्न्तगत पूर्व से जमा कूडे के निस्तारण व बायोमायनिंग/लैण्ड रिक्लेन के अर्न्तगत प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है। वर्तमान में नगर निगम के डम्पिंग साइट बीच शहर में हैं तथा भविष्य में भी इस स्थान के पूरी तरह से भर जाने पर नये डम्पिंग क्षेत्र/लैण्ड रिफिल साइट को तैयार करने में कठिनाई होगी। ऐसे में वायोमाइनिंग एक श्रेष्ठ विकल्प है जिसके माध्यम से डम्पिंग साइट को साफ कराकर पुनः इसी स्थान को आने वाले कई वर्षो के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट रूल–2016 के अनुसार फैक्ट्रियों में आर0डी0एफ0 के प्रयोग की बाध्यता है। बायोमाइनिंग की इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले आर0डी0एफ0 को भी सीमेन्ट फैक्ट्रियों के भेजा जाना है। मथुरा नगर से सीमेन्ट फैक्ट्रियों की दूरी तथा डम्पिंग साइट्स पर मौजूद कूडे की मात्रा लगभग 1.25 लाख टन के आधार पर इस परियोजना में लगभग 25 करोड रू0 व्यय होने की सम्भावना है। विस्तृत डी0पी0आर0 सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपुर्यक्त वर्णित धनराशि निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे कि विशेषज्ञ कम्पनियों से टैण्डर प्राप्त किये जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(समीर वर्मा) 18/9/18
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

प्रतिलिपि– मिशन निदेशक महोदय, नगरीय निकाय निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

Scanned by CamScanner

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन संकल्प सेवा समर्पण स्थापना-2017

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 1040 / एम० टी० / न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2019–20,   दिनांक : 09/12/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा

विषय   मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–588 / 2019 हेम सिंह योग सोशल वर्कर, पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन एवं श्री कौशल किशोर, पूर्व सभासद, नगर पालिका परिषद, मथुरा के पत्र दिनांक 11.11.2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री कौशल किशोर, पूर्व सभासद, नगर पालिका परिषद मथुरा के द्वारादिनांक 11.11.2019 को यमुनापार नगला कोल्हू स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट पर एकत्रित कूडे में आग जलने के कारण वायुप्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।उक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

बिन्दु सं0	बिन्दु विवरण	आख्या
1	स्थल पर MSWTSDF अवैध रूप से स्थापित कर देने के लिए मथुरा नगर निगम पर रू. 1 करोड 7 लाख जुर्माना आरोपित।	अवगत कराना है कि, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012 में मथुरा के नगला कोल्हू में 180 टन प्रतिदिन क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट (वेस्ट टू कम्पोस्ट) का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था सी0एंड डी0एस0 शाखा उ0प्र0 जलनिगम, मथुरा के द्वारा पूर्ण कराया गया। प्लांट निर्माण से पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्लांट के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 20.03.2009 को प्राप्त की गई। (संलग्न–1) ई0आई0ए0 अधिसूचना–2006 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से पूर्व जनसुनवाई भी की गई थी, परन्तु निर्धारित समयावधि अर्न्तगत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उसके उपरान्त सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2013 को अनापत्ति प्रदान की गई। शिकायतकर्ता का यह कथन कि प्लांट अवैध रूप से स्थापित किया गया है, असत्य एवं भ्रामक है।दिनांक 04.07.2019 को श्री डी0पी0 सिंह, मा अध्यक्ष, उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट कमेटी के द्वारा प्लांट का भ्रमण किया गया था, परन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जुर्माना आरोपित करने सम्बन्धी कोई सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है।

पत्र संख्या : / /न0नि0म0वृ0–मथुरा/2019–20, दिनांक :

2	1 सितम्बर 2019 से 6 माह अर्थात् 1 मार्च 2019 तक की अवधि के भीतर स्थल पर जमा कचरे के पहाडनुमा ढेर को जैविक उपचार के जरिए नष्ट कर साफ कर देना अन्यथा रू0 25,000 रोजाना के हिसाब से जुर्माना।	नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा डोर टू डोर कलैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग प्लांट संचालन एवं प्रबन्धन के लिए मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कं0लि0, मथुरा को प्लांट वर्ष–2013 में हस्तांतरित कर दिया गया। दिनांक 07.06.2014 में उक्त संस्था द्वारा प्लांट का संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य रोककर नगर पालिका परिषद के विरूद्व आर्बिटेशन का वाद दायर कर दिया (संलग्नक–2)। जिसके बाद नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिदिन जनित कचरा प्लांट पर ही एकत्रित किया जाने लगा। दिनांक 12 मई 2017 को उ0प्र0 शासन द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन का गठन किया गया। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उक्त संस्था को प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु आग्रह किया गया। प्रतिदिन जनित होने वाले कचरे के निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा पूर्व में अधिकृत संस्था मै0 मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कं0लि0, मथुरा से कोर्ट के बाहर आपसी समझौता किया गया। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निविदा के माध्यम से एस0वी0एम0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 संस्था का चयन किया गया। नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं समस्त उपकरण आदि माह मार्च 2019 में एस0वी0एम0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 को संचालन एवं प्रबन्धन हेतु हस्तांतरित कर दिये गये। इस अवधि तक प्लांट पर 01 एक लाख टन से अधिक कचरा एकत्रित हो गया, जिसके निस्तारण हेतु तकनीकी रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र सं0–1130 दिनांक 18.09.2019, अनुस्मारक सं0–1220 दिनांक 17. 10.2018, अनुस्मारक सं0–1562 दिनांक 12.02.2019, अनुस्मारक सं0–28 दिनांक 16.04.2019, अनुस्मारक सं0–235 दिनांक 25.05.2019, अनुस्मारक सं0–538 दिनांक 29.07.2019 एवं अनुस्मारक सं0–281 दिनांक 05.12.2019 द्वारा (संलग्नक–3) उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
3	उक्त MSWTSDF दूसरे स्थान पर UPPCB के परामर्श से SWM Rules, 2016 के अनुसार शिफ्ट करना तथा तत्काल प्रभाव से डम्पिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट को रोकना, जिससे क्षेत्रवासियों को कॉम्पलैक्स हैल्थ प्रॉबल्म्स से बचाया जा सके।	दिनांक 12 मई 2017 को उ0प्र0 शासन द्वारा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन का गठन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद वृन्दावन एवं मथुरा व 51 ग्रामों का विलय किया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शहरी कचरे के प्रबन्धन हेतु भूमि की तलाश की जा रही है। यहां यह भी अवगत कराना है कि, उक्त प्लांट के आस–पास के क्षेत्र में कई लोगों द्वारा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण से अनापत्ति/मानचित्र प्राप्त किये बिना भवन आदि निर्माण करा लिये गये हैं, उक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को पत्र सं0–232/1 दिनांक 06.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया है। (संलग्नक–4)

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : / /न0नि0म0वृ0–मथुरा/2019–20, दिनांक :

4	उक्त डम्पिंग साइट को अवैध तरीके से स्थापित करने की अनुमति देने वाली ऑथोरिटी पर एन0जी0टी0 जैसा उचित समझे मुआवजा आरोपित करेगी।	नियमानुसार ई0आई0ए0 अधिसूचना–2006 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से पूर्व जनसुनवाई भी की गई थी, परन्तु निर्धारित समयावधि अर्न्तगत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उसके उपरान्त सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2013 को अनापत्ति प्रदान की गई। जिसके बाद ही प्लांट संचालन कार्य प्रारम्भ कराया गया है। (संलग्नक–1)
5	नगर निगम मथुरा को तत्काल प्रभाव से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जलाये जाने से रोकने के निर्देश दिये गये।	नगला कोल्हू प्लांट पर एकत्रित कूडे पर में मीथेन गैस उत्सर्जित होने के कारण आग लग जाती है, आग लगने से रोकने के लिए कूडे की कैपिंग एवं मिट्टी की ढलाई करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्लांट पर आग बुझाने के लिए 02 समरसिबल पूर्व से ही स्थापित हैं, इसके अतिरिक्त 02 समरसेबिल लगवायी जा रही हैं। आवश्यकता पडने पर पानी के टैंकर से भी पानी का छिडकाव कर आग को लगने से रोका जाता है। आग लगने पर तत्समय आग बुझवा दी जाती हैं। वर्तमान में प्लांट पर किसी भी प्रकार का कचरा नहीं जल रहा है।
6	सी0एम0ओ0 मथुरा अपनी टीम के साथ क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे तथा फिजीकल एलिमेन्ट्स फाइन्ड आउट जिससे वे पीडित हैं। मॉनिटरिंग कमेटी को रिपोर्ट करेंगे।	उक्त बिन्दु के संदर्भ में कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से प्रस्तावित है।
7	सी0पी0सी0वी0 और यू0पी0पी0सी0वी0 की एक टीम उद्देश्यों/सिफारिशों और माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों को सुनिश्चित करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए बनायी जायें।	उक्त बिन्दु के संदर्भ में कार्यवाही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रस्तावित है।

संलग्न–यथोपरि।

9/12/19

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

Objective:

With an aim to make India clean, the Swachh Bharat Mission (Urban) was launched by the Government of India on 2nd October 2014. One of the key goals of the mission is to achieve 100% scientific processing of Municipal Solid Waste (MSW).

As per the goals and objectives of the Swachh Bharat Mission, Nagar Nigam Mathura-Vrindavan, Mathura wish to undertake **Bio-mining** of landfill located at Vill. NaglaKolhu, Mathura.

Salient details of the said landfill are as below:

a) Size of Land – 15 Acre.
b) Estimated amount of waste already collected at dumpsite 150,000 MT (Approx.).
c) Land owned by Nagar Nigam Mathura - Vrindavan.
d) Age of dumpsite 10 years.

Nagar Nigam Mathura Vrindavan is generating more than 210 tons/day (TPD) of municipal solid waste (MSW), which is disposed in the open area of Solid Waste Management Plant located at NaglaKolhu, Mathura, site having total area of 15 Acres, out of this untreated waste is dumped in 10-acre open area, which was established as an Integrated Waste Processing Plant in 2012. The capacity of existing plant is 140 TPD waste processing plant was installed for processing of incoming waste, whereas a small Sanitary landfill covering an area of 15,000 Sqm was developed to fill the residual inert coming from processing plant. The Plant of NaglaKolhu was become operational for use in December 2012. However, in 2013 the concessionaire stopped operating Processing Plant thereafter mixed waste dumping at this site is in progress. As of now approximately 10 Acres of area has covered with unprocessed waste with a dumping height ranging from 3 to 5 meters. The accumulated waste in this dumpsite is estimated about 1.5 Lakh MT. This site is still operating and receiving waste from entire jurisdiction of Nagar Nigam Mathura Vrindavan. The waste is being deposited randomly without any compaction and pollution prevention measures.

The focus of this project is scientific disposal of dumped waste at the processing site NaglaKolhu, Mathura City through following options. Nagar Nigam is going to stop unscientific disposal on the site. This project aimed to dispose dumped waste in the scientific manner and to restart the existing Integrated Waste Processing Plant. Although a significant portion of the deposited material shall have decomposed already or may be burned. It is estimated that still some amounts of biodegradable material have remained;NNMV intends to decompose the remaining biodegradable portion in scientific manner and proper disposal of non-biodegradable substances as well as inert material.

Existing Technologies for Dumpsite Remediation:

Below are the existing technologies used all over the world for Dumpsite Remediation:

- Bio-mining
- Capping of landfill
- Power from Landfill Gas

Evaluation of the Above Models:

On the detailed understanding of the above Remediation models for NaglaKolhu MSW Dump which is a mix waste the most suitable model of remediation of Dump at NaglaKolhu is Bio mining.

Bio-mining:

Bio-mining/ Landfill-mining and reclamation (LFMR) is a process whereby solid wastes which have previously been land-filled are excavated and processed. The function of landfill mining is to reduce the amount of

fill mass encapsulated within the closed landfill and/ or temporarily remove hazardous material to allow otective measures to be taken before the landfill mass is replaced. In the process, mining recovers valuable ecyclable materials, a combustible fraction, soil, and landfill space. The aeration of the landfill soil is a secondary benefit regarding the landfill's future use. The combustible fraction is useful for the generation of power. The overall appearance of the landfill mining procedure is a sequence of processing machines laid out in a functional conveyor system. The operating principle is to excavate, sieve and sort the landfill material.

The concept of mining was introduced as early as 1953 at the Hiriya landfill operated by the Dan Region Authority next to the city of Tel Aviv, Israel. Waste contains many resources with high value, the most notable of which are non-ferrous metals such as aluminium cans and scrap metal. The concentration of aluminium in many landfills is higher than the concentration of aluminium in bauxite from which the metal is derived.

India's innovative approach to land reclamation of old waste dumps by Bio-mining eliminates leachate and landfill gases by shaving off old waste from the top down, or from one side in cliffs, and forming the loosened waste into bio-treated aerobic windrows for almost total separation of waste leading it to scientific method of reuse or disposal of separated products. Ultimately the land is reclaimed.

Advantages of Bio- mining:

This has many benefits, described below, to:

- Increase available post-closure area for a new scientific landfill or alternate use.
- Achieve near-zero emissions of methane and leachate.
- Clear the site of old waste at less than one-tenth the cost of conventional capping and totally avoid the high annual costs of landfill management, leachate treatment and gas monitoring.
- Drastically minimize the volume of old waste needing permanent burial and the requirement of scarce land for this.
- Recycle both organics and buried recyclables. Organics become converted to soil-enriching bio-earth.
- Achieve all this in 3 year or less, compared to 30-year closure management of old landfills. Site clearance by bio-mining can commence at many points simultaneously if closure is very urgent.
- Avoid the insurance costs and potential liabilities for explosion-prone capped sites
- Leave no pollution problems or environmental time-bombs for future generations.
- Reduce the infiltration of precipitation into the landfill to control leachate generation;
- Minimize fugitive emissions of landfill gas through the surface of the cap (in Combination with an active gas abstraction system); Separate the waste in the landfill from its surrounding environment.

Bio-mining as a Safe Alternative to Capping:

Bio-mining or bio-remediation of waste dumps to produce near ZERO emissions and ZERO leachate by totally recovering and recycling all the waste from the levelled site, leaves only limited rejects or no rejects and no problems for future generations, with maximum recovery or complete recovery of usable space. This is a recent cost-effective technology fine-tuned in a hitherto developing country. So the initial investment, time and effort needed to make this very eco-friendly option eligible for Carbon Credits. It is now necessary for all the bio-mining operators along with the Govt. of India to take the lead in ensuring that this fully well-proven bio-mining option becomes eligible for Carbon Credits.

Given all the advantages listed above, it is better to abandon all thought of capping as an option for NNMV and other open dumps and adopt bio-mining instead. Hopefully within a year some progressive Carbon Credit trader may complete the arithmetic and paperwork for claiming global Carbon Credits via the eco-friendly bio-mining route, based on the Total Avoidance of potential methane generation from the entire volumes of waste in landfills which will be stabilized by bio-mining.

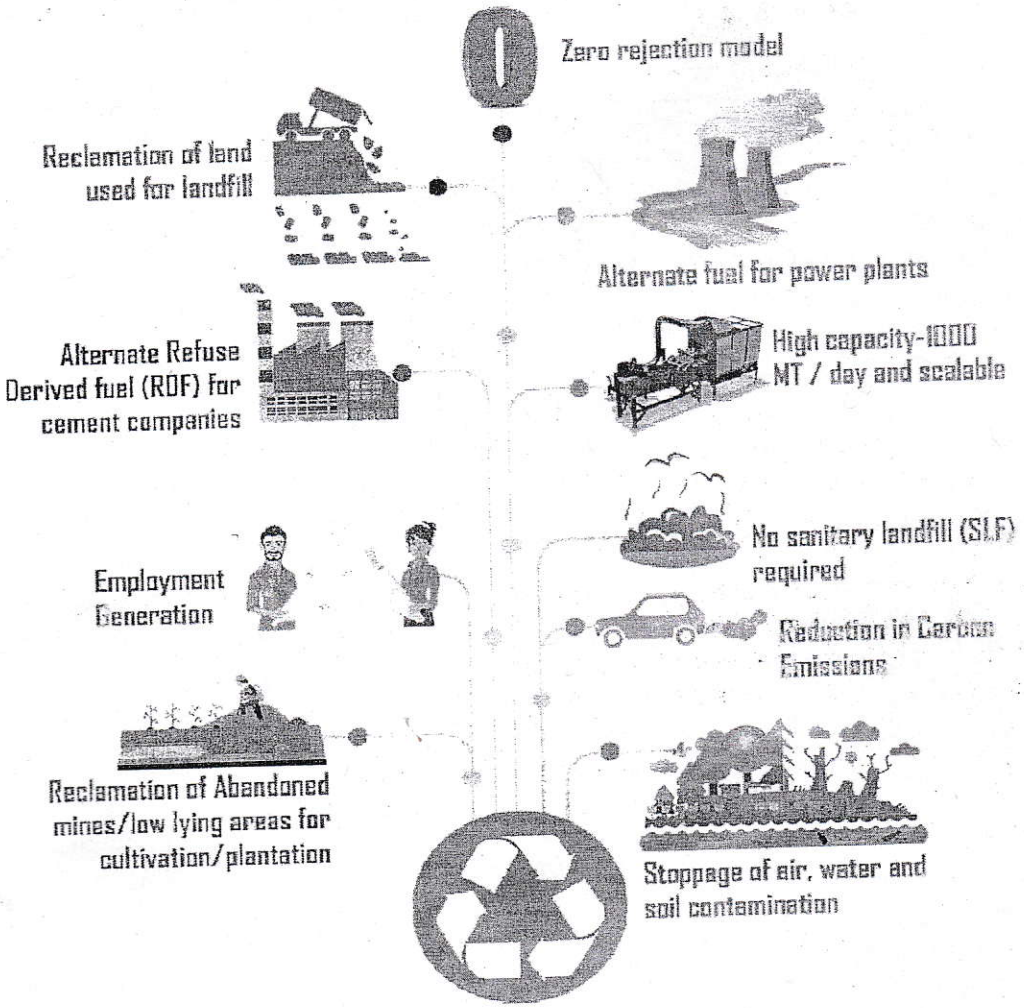

Bio-mining has many win-win benefits, described below, to:

- Increase available post-closure area for a new scientific landfill or alternate use.
- Achieve near-zero emissions of methane and generation of leachate.
- Clear the site of old waste at less than one-tenth the cost of conventional capping and totally avoid the high annual costs of landfill management, leachate treatment and gas monitoring.
- Drastically minimize the volume of old waste needing permanent burial and the requirement of scarce land for this.
- Put to better use both organics and buried inorganics. Organics become converted to soil-enriching bio-earth and inorganics can be either recycled or converted into Alternate Fuel.
- Achieve all this in one year or less, compared to 30-year closure management of old landfills. Site clearance by bio-mining can commence at many points simultaneously if closure is very urgent.
- Avoid the insurance costs and potential liabilities for explosion-prone capped sites
- Leave no pollution problems or environmental time-bombs for future generations.
- Technology and Process.
- Preliminary design and preliminary working drawing, to suggest right type of equipment machinery/ method for remediation of the dumpsite.

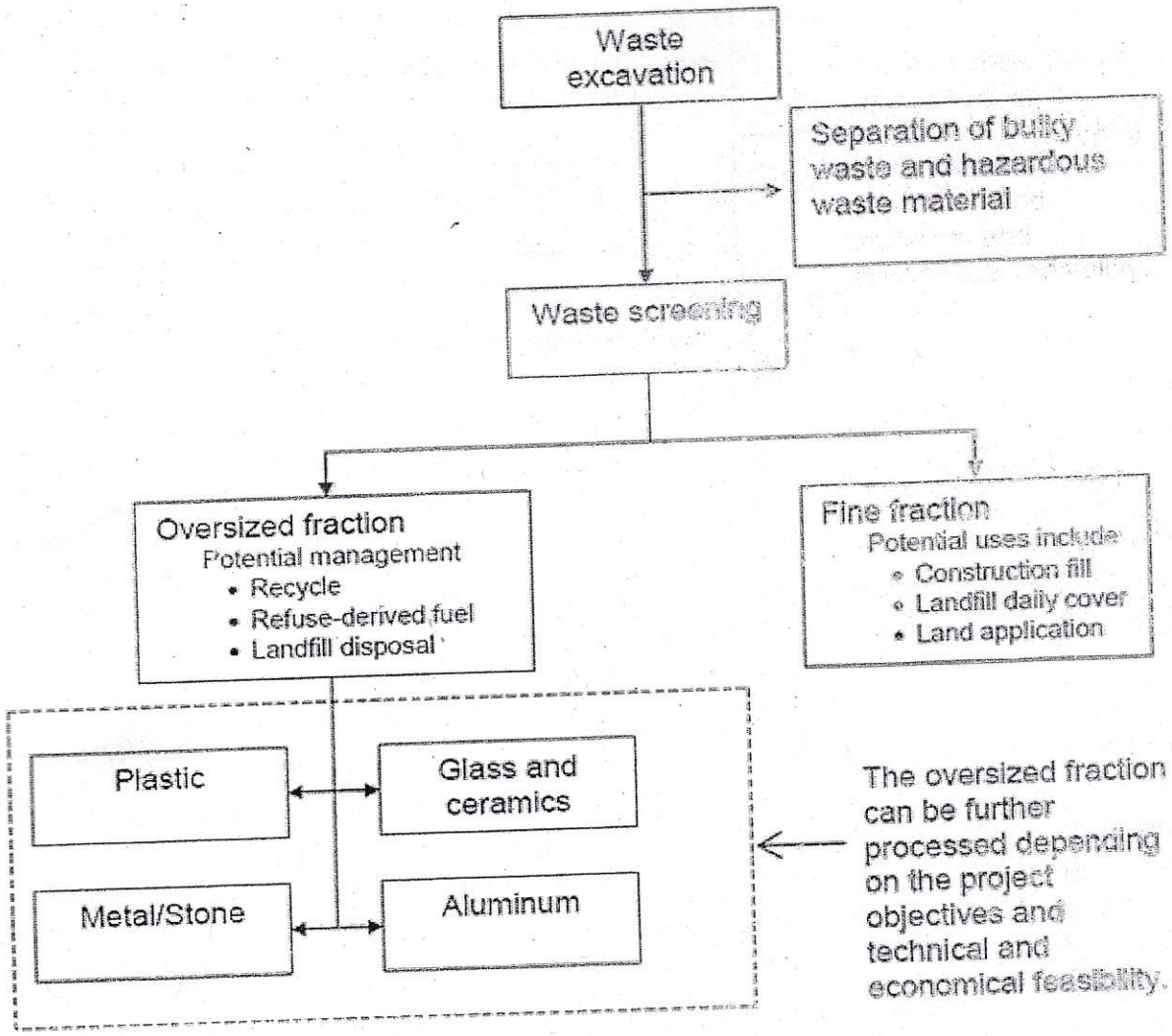

FIGURE 1Bio-Mining Project

above flow chart provides the brief idea about the two major classifications of final products obtained in the landfill mining the are Fine fractions / Non Combustibles Inerts and Oversized Fraction there are two major Divisions C & D waste and Combustibles Depending on the efficiency of the machinery used it is important to understand that the other category is evolved which play an important role while evaluating the company is Percentage Rejects this category comes into picture due to certain limitations of the machinery to effectively segregate the waste.

Parameters:

The adoption of the technology or method for remediation is dependent on the following parameters:

- Composition of waste
- Quantum of waste
- Processing Efficiency
- Support Infrastructure
- Legal and environmental framework.
- Cost Effectiveness

Composition of Waste:

In general, it has been observed that on analysis of the existing waste large percentage (approx 75%) of the MSW content consist of Compost and Inerts. The detailed analysis by sampling at the various levels of the existing waste needs to be carried out for deriving the physical and chemical characteristics.

Quantum of waste:

Mathura is a city in the North Indian state of Uttar Pradesh. It is located approximately 50 kilometres north of Agra, and 145 kilometres south-east of Delhi; about 11 kilometres from the town of Vrindavan, and 22 kilometres from Govardhan. It is the administrative centre of Mathura District of Uttar Pradesh. During the ancient period, Mathura was an economic hub, located at the junction of important caravan routes. The 2011 census of India estimated the population of Mathura to be 441,894.

Mathura is the birthplace of Krishna at the centre of Braj or Brij-bhoomi, called Shri Krishna Janma-Bhoomi, literally: 'Lord Krishna's birthplace'. It is one of the seven cities (SaptaPuri) considered holy by Hindus. The KeshavDev Temple was built in ancient times on the site of Krishna's birthplace (an underground prison). Mathura was the capital of the Surasena Kingdom, ruled by Kansa the maternal uncle of Krishna.

Mathura has been chosen as one of the heritage cities for HRIDAY - Heritage City Development and Augmentation Yojana scheme of Government of India.

The waste generation in NNMV is 210 Metric tons (2017) and the waste generation is likely to grow over the coming years.

There was change of 22.78 percent in the population compared to population as per 2001. In the previous census of India 2001, Mathura District recorded increase of 25.68 percent to its population compared to 1991.

cessing efficiency:

The processing efficiency is of utmost importance for making the decision on adoption of the technology. The key aspects related to the efficiency are the following:

- The origin and quality of the waste (mixed, segregated or non-segregated)
- Presence of hazardous or toxic waste
- Category of the technology – Physical, biological, thermal or a mix of three.
- Time taken for processing the waste.
- Support infrastructure and manpower required for the processing
- Unit cost per Metric Tons for the processing.

Support Infrastructure:

The experience in the country in terms of waste treatment range from success stories at the pilot level to the moderate success at the large scale. The success factors can be attributed to the support infrastructure and institutional capacity. The projects for waste processing must be tested for the following:

- Engineering feasibility and operations
- Viability within financial inputs.
- Man power – technical inputs.
- Continuous input of the feed for continuous operation of the process.
- Ease in operations including enabling and obtaining permissions/ sanctions.

Further, the aspects related to the disposal of by-products are crucial.

Legal and Environmental Framework:

Bio-mining comply with the allowable technologies under the MSW2016 Act and necessary documentation and procedures must be followed for the tendering action. Within the given framework, the RFP and bidding may be adopted.

Cost Effectiveness:

Cost Effectiveness can be calculated on Overall Expense of the project. Quantity of Dump process, Value of Land recovered. Investment risk to ULBs.

Evaluation of Variables:

Land requirements for the Technology:

The responses range from the need of land of about 3 Acres to about 30 acres of land for setting up the Waste to power projects. For Bio mining about 1 acre of land is on average a requirement for 1000TPD Plant. A few ancillary buildings associated with processing are proposed at the cost of the operators.

Details of the R&D, patenting and licensing of the technology, etc.

Bio-mining is tested process and is very suitable. For the Bio-mining process- indigenous technology and equipment is available. The Waste to energy especially in the bio methanation process is patented to

earch institutions, etc. Licenses and technology transfer may be required for the operationalising the me.

Operation and Management Plan for the Project:

Man power staffing for the project including details of the manpower requirements (Skilled and Unskilled) and plans for sourcing such as manpower locally for the project. The plan suitable is for sourcing the talent locally. The skilled ones are to be brought from their respective joint venture partners. As the players may not be available at all times, it may be possible not to depend technologies that require intense, dependence on the foreign technologist. The operation and management costs include the salaries to the workmen, the maintenance of plant and machinery, etc. This is expressed as per the per Metric Ton basis.

NNMV Contribution:

Expectations of the private entity for making the waste processing are mapped. The expectations include the concession period, payment of processing fee, clearances, approvals, Power Connection, permits and lease of land.

Cost Criteria:

Cost Criteria, Capability of working in Indian environment, time bound execution, history, strength, and experience in India and abroad, financial capability is captured in the evaluation.

Application of recovered material (RDF, Reclaimed Soil/ Bio Earth and C&D Waste):

As the process of Bio-mining starts Combustibles, Bio-earth and C&D waste are separated. These products are of very less commercial value. The major responsibility of entity performing the task of Bio-mining is to scientifically dispose the recovered material.

Refuse-Derived Fuel (RDF):

RDF consists largely of combustible components of such wastes, as non-recyclable plastics (not including PVC), paper cardboard, Cotton, labels, and other corrugated materials. These fractions are separated by different processing steps, such as screening, air classification, ballistic separation, separation of ferrous and non-ferrous materials, glass, stones and other foreign materials and shredding into a uniform size, in order to produce a homogenous material which can be used as substitute for fossil fuels in e.g. cement plants, lime plants, coal fired power plants or as reduction Agent in Steel Furnaces.

Yet it is the case, that worldwide there is no exact classification or specification which is used for such materials. Even legislative authorities have not yet established any exact guidelines on the type and composition of alternative fuels. The first approaches towards classification or specification are to be found in the Federal Republic of Germany as well as at European level (European Recovered Fuel Organization). These approaches which are initiated primarily by the producers of alternative fuels follow a correct approach. Only through a strictly and exactly defined standardization in the composition of such materials can both production and utilization be uniform worldwide.

use Derived Fuel (RDF) is mainly used as alternative fuel resource in cement factories and Power ants. The key consideration in selecting these two for the consumption of RDF is the temperature. For scientific disposal of RDF it should be burned at the temperature above 900 Degree Celsius.
Generally it is found that the RDF generated from an efficient Bio mining process would have (a) moisture levels less than 15% and (b) Calorific Value exceeding 2500 Kcal/Kg making them a very good source of energy alternate to fossil fuels.

Reclaimed Soil/ Bio Earth:

Bio-earth is the fine fraction (4mm to -12mm) received from the landfill mining of MSW. It is the completely decomposed organic matter and possesses strong water holding capacity. This is helpful for growth of crops in fields. Thus this fraction of inert can either be conditioned to sell as compost or can be directly given to nearby farmers for its use in farm. This is also been seen as an excellent supplement to convert barren lands into fertile and as a filler material for normal and highly quality composts that are manufactured in the market.

Investigation of Physio-Chemical Characteristics:

It is important to understand the contents in reclaimed soil as it may contain heavy metals, biodegradable matter. On the confirmation of waste characteristics the decisions of disposal of bio-earth can be taken. The following table is an example of waste characteristic study done by Anna University.

Table 1Physio-chemical characteristics of the soil fractions of MSW from PDG

Particulars	Augur *			Excavation **		
	Min	Max	Ave ± SD	Min	Max	Ave ± SD
Temperature (°C)	32	39	35 ± 5	34	36	35 ± 1.4
Moisture content (%)	21.4	52	39.5 ± 9.5	19	40	30 ± 6.1
pH	7.6	8.6	8.06 ± 0.29	7.2	8.2	7.8 ± 0.28
VOM (g/kg)	89	158	117 ± 21	63	144	111 ± 21
Ash content (g/kg)	842	911	883 ± 21	856	937	889 ± 21
TOC (g/kg)	52.3	78.8	55.6 ± 9.4	30.2	69.1	53.2 ± 10.2
Dry density (kg/m³)	745	1147	965 ± 132	809	1185	995 ± 85

As the material is of very low commercial value in case of Vadodara it can be used for filling up the low lying areas. As per the Guidelines of NHAI it can also be used for National highway embankment purpose.
The soil that was used as daily and/or intermediate cover during landfilling operations and the degraded organic matter typically constitutes more than 50% of the material recovered from MSW landfills (on a weight basis). Potential reuse options for the recovered soil include use as daily and intermediate landfill cover material (uses inside the landfill) and as construction fill (uses outside the landfill). Other end uses will be dictated by available markets, the quality of the material, and the regulatory framework for reuse. The issue that would most likely limit the reuse of mined landfill fines for use outside of the

ıdfill environment would be the presence of trace chemicals. Given that a large variety of household, ommercial, and industrial waste containing chemicals are disposed of in MSW landfills, the potential impact of these chemicals on the environment if the mined residues were reused must be considered. When evaluating the likely chemicals of concern, it should be noted that most organic chemicals should eventually be biodegraded in the biogeochemical environment of a landfill. Non-degradable chemicals such as heavy metals, however, will remain in the waste unless leached out. Several investigations indicate that heavy metals would be retained in the landfill. The concentrations of these chemicals in the mined material would likely dictate the degree mined residue can be reused outside of the landfill environment. No federal regulations specific to the reuse of materials mined from a landfill exist. The reuse of waste materials as a replacement for soil will depend on the regulations and policies of the individual state or territory where the application is proposed. Typically, the concentration of chemicals in the fines would have to be characterized to assess the risk to human health from direct exposure of the material if it is reused in the environment and the risk to groundwater or surface water.

The process used in many states is to compare a concentration that is statistically representative of the material proposed to be reused (e.g., the 95% upper confidence limit (UCL)) to a health-based risk level. Health-based risk levels for soil, known as the soil cleanup target levels (SCTLs) have been published by the Florida Department of Environmental Protection. Two categories are published by the FDEP, one for residential settings (the more stringent of the two) and one for commercial/industrial settings. These values are different because a different set of exposure assumptions were used in the risk assessment; less human exposure is expected to occur in the commercial/industrial setting. If a waste material was proposed for reuse, a typical process would be to compare the 95% UCL for the constituents of concern (the list of constituents may be determined on a site-specific basis) to the SCTL to determine appropriate reuse. For use in commercial/industrial settings, some assurance would need to be provided that the property where the material was being reused remained commercial/industrial (known as institutional controls). To evaluate the potential risk to groundwater or surface water, the reused material may be tested for leachability and compared to the clean-up target levels for groundwater and surface water.

A limited number of investigations have also been conducted to characterize the chemical characteristics of materials reclaimed from MSW landfills. Stabilized residues from a MSW test cell in Sweden were characterized for heavy metals. Mercury levels in stabilized residues from a MSW landfill in Florida have been reported. Kilmer and Tustin (1999) measured the metals content for three solid waste samples collected from a bioreactor landfill in Worcester County, characterized six samples of residue from an aerobic bioreactor test cell in Georgia that passed through 19.1-mm and 9.5-mm (3/4-inch and 3/8-inch) screens for (2005) characterized soil passing through a ¼-inch screen for samples collected from a landfill in Florida. Table 2-2 summarizes the heavy metal content of fine materials reclaimed from MSW landfills for several studies reported analysed three fractions of waste samples collected from an MSW landfill: a fine fraction (<0.425 mm), an intermediate fraction (>0.425 mm and <6.3 mm), and a fraction consisting of paper products that could ultimately degrade to a smaller size. The intermediate fraction consisted of degraded organics such as wood or paper, while the fine fraction was more soil-like. In general, the metal concentrations were greatest in the intermediate fraction and lowest in the fine fraction. The effect of sample age on the metals content was also investigated. The concentrations of several metals were greater in older samples (approximately eight years old) than in newer samples (approximately three years old). Limitations associated with the land application of residual soil (composed of the fine and intermediate fractions) were assessed by comparing measured concentrations to SCTLs. Table 2-2 presents metals content of reclaimed soil reported by Kilmer and Tustin (1999), Earle et al. (1999), Das et al. (2002), and Jain et al. (2005). Depending on the particular site, the degree of waste screening, and the type of cover soil, it is not unreasonable that recovered fines from mined landfills may have viable reuse options outside of the landfill (in addition to the reuse

ions inside the landfill such as cover soil). However, site-specific testing to obtain regulatory approval hould be conducted before reusing these materials.

C&D Waste (or Inerts):

The use of these materials basically depends on their separation and condition of the separated material. A majority of these materials are durable and therefore, have a high potential of reuse. It would, however, be desirable to have quality standards for the recycled materials. Construction and demolition waste (inerts) can be used in the following manner:

- Reuse (at site) of bricks, stone slabs, timber, conduits, piping railings etc. to the extent possible and depending upon their condition.
- Rubble, brick bats, broken plaster/concrete pieces etc. can be used for building activity, such as, levelling, under coat of lanes where the traffic does not constitute of heavy moving loads.
- Larger unusable pieces can be sent for filling up low-lying areas like quarries, clay soil mining areas and mining site reclamations. · Fine material, such as, sand, dust etc. can be used as cover material over sanitary landfills and National Highway Embankments

Rejects:

Rejects are the outcome of limitation of machinery, technology used for landfill mining. It consist of complete mix of MSW hence cannot be categorized in any of the above. On Storage it can generate leachate, hazardous gases so it needs to be stored in SLF. Percentage of Rejects defines the effectiveness of the processing capacity of the machinery. The ideal scenario in landfill mining is when there are zero percent rejects or no rejects.

For NNMV it important to select the company with technology of zero percent rejects otherwise there will be expense of making SLF which consumes land, time and money.

Detailed Project Implementation Schedule and Process of Land Reclamation

Schedule of Implementation

The table below explains the detailed schedule to be followed for implementation of the remediation process. The first three months are the mobilization period which is required to prepare the site, obtaining requisite licenses, power connection and handling over of the site. In the first year, the work include the processing of the 0.5 lakh tonne waste and 1.0 lakh tonne waste in the second year.

Detailed Project Implementation Schedule

TIME TAKEN	WORKS
Mobilization Period: First 3 months	This time is required for preparing the site, Pre-assessment and geotechnical studies, obtaining requisite licenses, Power connection and handing over of the site.

st year (including the 3 months mobilization eriod)	Processing 0.5 Lakh tonnes
Second Year	Processing 1.5 lakh tonnes

The following assumptions have been made while preparing the schedule:

- Undue monsoons can delay the process considerably as Bio-mining requires the material to be dry for processing.
- Any kind of natural calamities might delay the process as the machineries are not placed in permanent structures and damages can be disastrous.
- Time taken for clearances are indicative and might prolong based on place to place.

Process of Reclamation of Land:

Dumpsite Reclamation or Mining is the process of excavating from operating or closed solid waste landfills, and sorting the unearthed materials for recycling, processing, or for other dispositions. It is the process whereby solid waste that has been previously land filled is excavated and processed.

Objectives of Dumpsite mining are as follows:

- Conservation of landfill space.
- Reduction in landfill area.
- Elimination of potential contamination source.
- Rehabilitation of dump sites.
- Energy recovery from recovered wastes.
- Reuse of recovered materials.
- Reduction in waste management costs.
- Redevelopment of landfill sites

Technically, dumpsite mining employs the method of open cast mining for sorting out the mixed material from the landfill according to their size by using a screening machine. The oversized materials are pre-screened by another sorting machine which separates the larger objects like tyres and rocks from cardboards and other smaller unearthed materials.

Dumpsite mining also provides the opportunity to remediate public health and environmental quality problems associated with the existing or closed facility (e.g. groundwater contamination). It will allow the placement of a lining system in unlined dumpsites and landfills so that future processes and solid waste management activities undertaken at the site might not present any unmanageable risk to public health and environmental quality.

The key to dumpsite mining operation is a set of conveyers and screens that sorts the solid wastes into three fractions: oversized material, intermediate-sized waste, and dirt/humus. The oversized materials consist of recyclable metallic goods, white goods, plastics and rubber. The intermediate-sized materials consist of partly decomposed organics, combustibles, recyclables and the fine fraction will mostly be stabilized soil. The main part of the process is the screening where the main separation is done for the oversized and the soil elements. Ferrous metals are generated from the main stream by employing a

gnetic separator and the non-ferrous parts using an air classifier, which leaves behind the residue nat could be combusted.

In dumpsite mining operations, an excavator removes the contents of the landfill cell. A front-end loader then organizes the excavated materials into manageable stockpiles and separates out bulky material. A trommel (a revolving cylindrical sieve) or vibrating screen separates soil (including the cover material) and solid wastes from the reclaimed waste. Trommel screens are more effective than vibrating screens for basic landfill mining. The size and type of screen used depends on the end use of the recovered material. For example, if the reclaimed soil were to be used as landfill cover, a 6.25 mm screen is used for separation. A smaller mesh screen (2.5 mm) may be used to remove smaller pieces of metal, plastic, glass, and paper, if the reclaimed soil were meant for construction fill, or for another end use requiring fill material with a high fraction of soil content.

The separation of dirt/ humus material from the intermediate- sized waste is made using a screen grid with 6.25 mm openings. The success of materials recovery is dependent on the composition of the waste, the effectiveness of the mining technology and the efficiency of the technology. The recovery of various materials ranges from 50 to 90% of the waste. The average soil fraction in recovered municipal waste from landfill tends to be around 50-60%. However, it can vary between 20 and 80% as given in Table 5.2 depending on moisture content and decomposition rate. The soil fraction could be used as cover or lining of new landfill. It is suggested by experts that a landfill needs to be 15 years old before a successful mining project can be performed. The success of a project depends on the composition of the decomposed waste.

The non-recyclable part of the intermediate-sized and oversized materials is typically reburied in the mined area of the landfill. If this portion is reburied without further processing, this landfill mining operation typically achieves about 70% volume reduction. Facility operators considering the establishment of a landfill mining and reclamation program must weigh the several benefits and drawbacks associated with this waste management approach

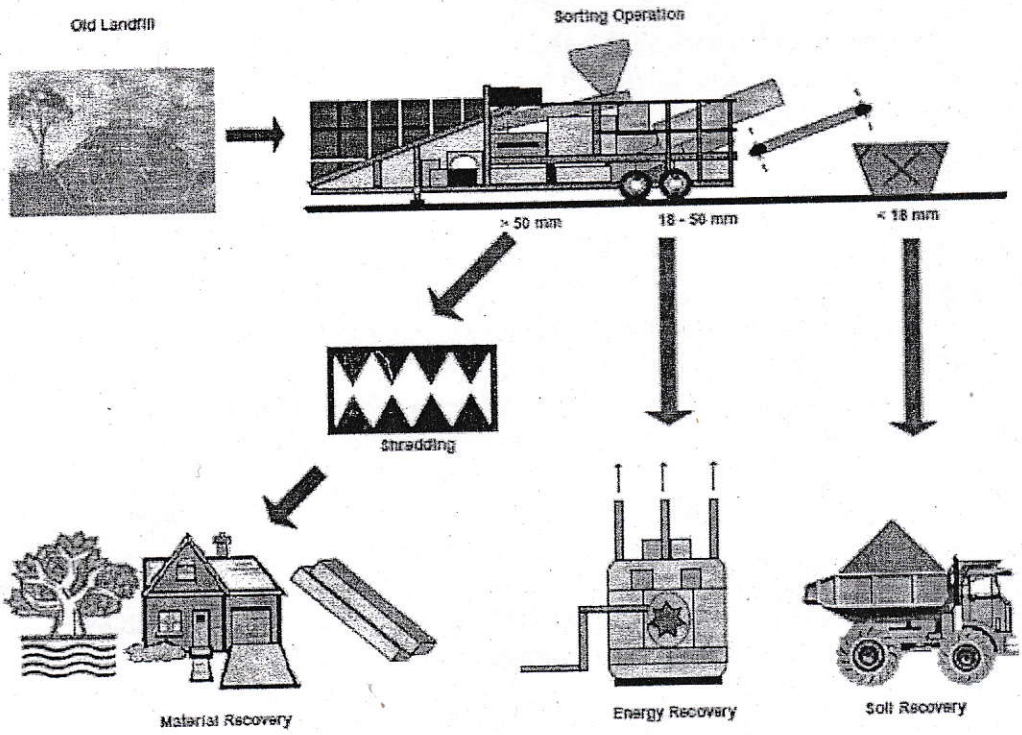

Schematic of landfill mining process

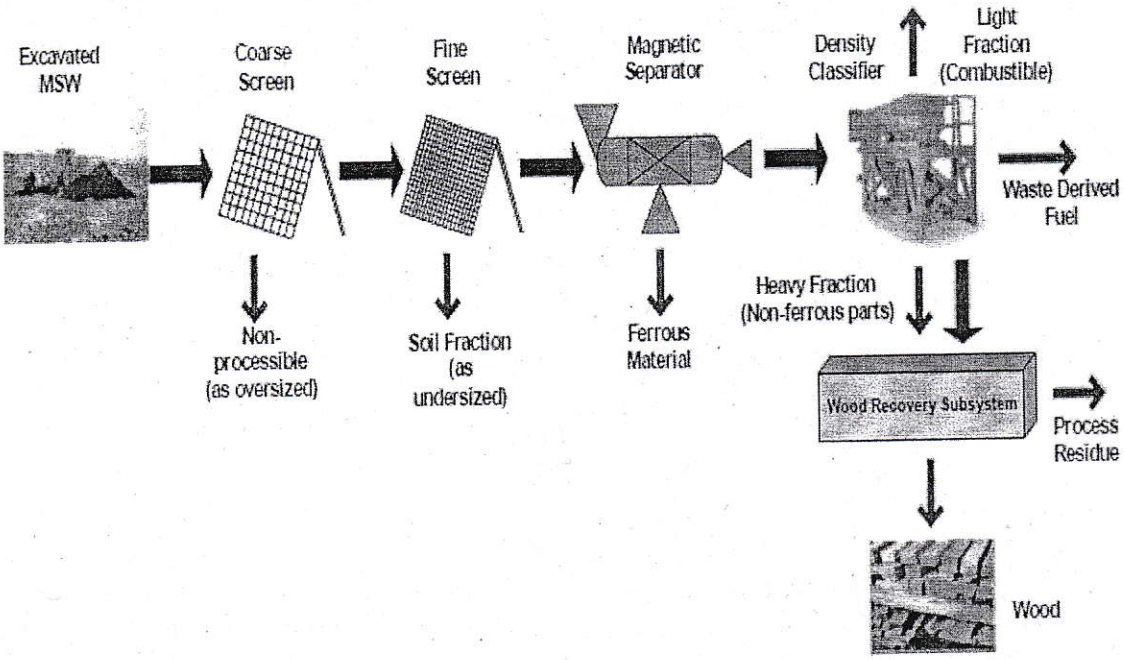

Process Scheme for a Landfill Mining Plant

...tions for Utilization of Recovered Land:

On completion of Bio mining of the MSW the land recovered is supposed to treated for its stability and can be used for many different applications as per the priority of ULB. In South Korea such reclaimed lands were used for building Commercial Complex, constructing stadiums, subway stations and secured landfill sites.

In case of NNMV the land the surroundings of the dumpsite are developing in modern residential buildings. NNMV can plan to construct a full-fledged Solid Waste Management facility complex involving Compost Plant for organic waste, Bio-methanation plant for slaughterhouse waste, Waste to Energy Plant for mixed waste, Leachate Treatment Plant, Sanitary Landfill site and all other ancillary facilities. A permanent green belt may also be planned to ensure that there is considerable amount of effort to attract flora and fauna at the site. A similar greenfield project has been executed at Saligao in Goa after Bio-mining by Hindustan Waste Management Corporation Private Limited, Goa.

Operational Cost of Landfill Mining:

The best model that the ULB can adopt would be on DBFOO (Design, Build, Finance, Own and Operate) Model wherein we do not seek any funding from the ULB's for capital expenditure. Since, all machines are mobile, except for civil foundations and structural, the contractor would be able to retrieve the entire set of equipment once the project is completed. Again, a ULB does not require Landfill Mining machinery once the project is complete, so we have embarked upon this kind of model.

The operational cost has two components, namely:

1. Cost for Stabilization, Segregation and Processing
2. Cost for responsible disposal of aggregates

NNMV has to take a call on whether it is interested in completely outsourcing the process or take care of disposal of aggregates with them. RDF can be ideally utilized if there is any future proposal for NNMV for setting up a Waste to Energy plant. The Agreement with the Concessionaire could be such designed mentioning that the Company would be obligated to utilize the RDF that is being generated from the Bio-mining process.

The inert material that is generated can be utilized for soil cover for the existing waste, road embankment, building parks, filling up low lying areas.

Cost for Stabilization, Segregation andProcessing will vary between **Rs. 600 to Rs. 675 per MT** and **Cost for responsible disposal of aggregates**, in NNMV the same would vary between **Rs. 1,600 to Rs.1750 per MT.**

Project Cost:

In reclamation project of dumpsite the capex involved is only on the machineries which are modular and movable, thus, post reclamation the machineries are transferred to the another site and as such the operator does not wish to have a capex support on such projects. Thus, the project cost will be on the OPEX for the entire reclamation activities i.e. (total legacy waste) X (total estimated opex) = (total project cost).Thus, OPEX estimation is as under:

A. Bio-Mining Cost:

Sl. No.	Description	Cost Per Ton (In INR)
1.	Power	39
2.	Material Handling	182
3.	Pre-Processing and Stabilization	65
4.	Manpower	67
5.	Finance & Administration	154
6.	Miscellaneous & Contingencies (Includes machinery Maintenance, fire management, leachate treatment, online monitoring and Pre/Post/Interim assessment studies	80
7.	Contractor Margin	50
8.	**Total Bio-Mining Cost Per Ton (A)**	**637**

B. Disposal Cost:

Particulars	%	In MT	Disposal Freight Cost/ Truck	Qty./ Truck (In MT)	Disposal Cost per MT	Total Cost (In INR)
Total Qty. of Waste		150000				
Total Qty. of RDF	32%	48000	37000	12	3083	147984000
Total Qty. of Inerts	68%	102000	2500	12	208	2121600
Total Cost to Disposal						150105600
Disposal Cost per MT (B)						**1128**

Total estimated legacy waste at identified dumpsites: Approx. **1,50,000metric tons**
Total estimated Opex cost Estimation (A+B) : **Rs. 1765.00/MT**
Total Project Cost of dumpsite remediation/ reclamation: **Rs. 26.48 Crore**

Here, it is clarified that the estimated legacy waste is derived post topo-survey and through statistical calculation.

Other Project Specific Benefits:

Real Estate:

The total land area that would be reclaimed as a result of Bio-mining at NaglaKolhu is..... acres and the current Commercial Value per acre at the dumpsite is Rs..... Hence, the real estate cost itself works out to be Rs..... against the Project Cost of Rs.26.48 Crore.

60

ermanent relief from Fire, Odour and Flies

Since the first step of Bio-mining would involve stabilization of the dumpsite thus the resulting fire, odour and fly problems will be addressed within a short duration of time. Hence, the process would address temporary as well permanent problems of the NNMV on a long-term basis.

SL. NO.	DESCRIPTION	COST PER TON (IN INR)
1	Power	39
2	Material Handling	182
3	Pre-processing and Stabilization	65
4	Manpower	67
5	Finance and Administration	154
6	Miscellaneous & Contingencies (includes machinery	80
7	Our Margin	50

TOTAL (B)	637

		(in MT)		Disposal Freight cost per truck	Qty per truck(in MT)	Disposal Cost per MT	Total Cost (in INR)	Cost against Processing Fees
Total quantiy of Waste		1,25,000						
Total quantity of RDF	32%	40,000		37,000	12	3,083	12,33,33,333	**986.67**
Total quantity of Inerts	68%	85,000		2,500	12	208	1,77,08,333	**141.67**

TOTAL (B)	1128.33
TOTAL (A)	637.00
	1,765.33

Please note:

1. The RDF produced will be sold to Ambuja, Kymore MP. Distance is 640 kilometers.
2. The plant can begin operation only from December 2018.
3. Project period is 2 years for 1.25 lakh tonnes.
4. Mobilisation advance: 25%

59

SL. NO.	DESCRIPTION	COST PER TON (IN INR)
1	Power	39.00
2	Material Handling	182.00
3	Pre-processing and Stabilization	65.00
4	Manpower	67.00
5	Finance and Administration	154.00
6	Miscellaneous & Contingencies (includes machinery maintenance, fire management, leachate treatment, CCTV surveillance, Online Monitoring and Pre/Post/Interim assessment studies)	80.00
7	Contractor Margin	50.00
	TOTAL	**637.00**

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय : नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्र संख्या : 232/1/स.न.आ./न0नि0म0वृ0–मथुरा / 2019–20 दिनांक : 06-5-2019

सेवा में,

सचिव,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।

महोदय,

अवगत कराना है कि, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगला कोल्हू में प्लांट का निर्माण कार्य पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के भाग–11 के अर्न्तगत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के कर्तव्य निम्नानुसार लक्षित है– ***राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके 5 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करना।***

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश एवं उ0प्र0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 का अनुपालन कराया जाना है। परन्तु प्लान्ट के निकट ही कुछ लोगों के द्वारा भवन आदि का निर्माण करा लिया गया है एवं इन्हीं भवन स्वामियों के द्वारा समय–समय पर इस ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के खिलाफ शिकायत व प्लान्ट को स्थानांतरित कराने की मांग की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, नगला कोल्हू स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के आस–पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर निर्मित अवैध आवासीय भवनों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड

मथुरा।

पत्रांकः 963/ओ-47/2019 दिनांक 07/12/19

सेवा में,

संयुक्त नगर आयुक्त,
मथुरा–वृन्दावन, नगर निगम,
मथुरा।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–588/2019 हेम सिंह योग सोशल वर्कर, पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–588/2019 हेम सिंह योग सोशल वर्कर, पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सहा0 नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा दिनॉक 07.12.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन के प्रतिनिधि के रूप में श्री ए0के0 सिंह, सहायक नगर आयुक्त एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ के सैग्रीग्रेशन, ट्रीटमेंन्ट एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट को संचालित करने वाली संस्था मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा के प्रतिनिधि के रूप में श्री एम0के0 गर्ग, प्रबन्ध निदेशक उपस्थित थे। नगरीय अपशिष्ट भण्डारण एवं बायो कम्पोस्टिंग के दौरान प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के निस्तारण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण संयन्त्र स्थापित किये जाये। नगरीय ठोस अपशिष्ठ में समय–समय पर आग लगने के कारण वायु प्रदूषण एवं दुर्गन्ध की समस्या का निवारण किया जाये। नगरीय ठोस अपशिष्ठ के बायो कम्पोस्टिंग के दौरान जनित होने वाले लीचेड इफ्लूएन्ट के शुद्धिकरण की व्यवस्था स्थापित नहीं है जिसके रिसाव से भूमिगत प्रदूषण होने की सम्भावना है। भूमिगत जल के प्रदूषण से बचाव हेतु बायो कम्पोस्टिंग स्थल को पक्का कर दूषित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण हेतु उचित व्यवस्था की जाये। निरीक्षण के समय स्थल पर ठोस अपशिष्ट का ड़म्पिंग अनसाइन्टिफिक तरीके से किया जा रहा है जिससे लीचेड इफ्लूएन्ट के रिसने की पूरी सम्भवना है। ठोस अपशिष्ट का डम्पिंग स्थल सीमेन्टेड नहीं है। नगरीय ठोस अपशिष्ट लगभग 1.5 लाख टन जनित होता है जिसका नियमानुसार निस्तारण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्पेसिफिकेशन फार सैनेटरी लैण्ड फिल साइट स्थापित किए जाने हेतु नियम/गाइड लाइन निर्धारित किए गये हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा साथ ही साथ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 प्राविधानों अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) तथा नगरीय ठोस अपशिष्ठ–2016 के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।
3. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मै0 एस0वी0एम0 इन्फ्रा इस्टेट प्रा0 लि0 सेक्टर–73, नोएडा, को इस निर्देश के साथ कि नगरीय अपशिष्ट भण्डारण एवं बायो कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान वायु प्रदूषण के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

) प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड

मथुरा

पत्रांकः 971/P-179/19 दिनांकः 09/12/19

सेवा में,

श्री के0वेंकटेश, प्रेसीडेन्ट,
मैसर्स पैटर्सन एनर्जी प्रा0लि0,
खसरा सं0–77, 78 व 80, ग्राम–सहजादपुर,
ट्रान्स यमुना, लक्ष्मी नगर, मथुरा।

विषयः **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की धारा–25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तों एवं एस0ओ0पी0 की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण उद्योग की सहमति (जल/वायु) अस्वीकृत कर दी गयी थी। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 07.12.2019 को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं संयुक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन के साथ एवं दिनांक 09.12.2019 को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग निर्माणाधीन पाया गया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.12.17 द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एम0ओ0ई0एफ0, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से जारी Standard Operation Procedures में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुपालन करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति (जल/वायु) प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्लान्ट का संचालन अर्थात परीक्षण उत्पादन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार हो सके तथा साथ ही साथ पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कृपया नोट करें कि उपरोक्त का अक्षरशः अनुपालन न होने की दशा में उद्योग के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के स्वयं का होगा।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou]

eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou] eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou] eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou] eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou] eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA

ek0 jk"Vªh; gfjr vf/kdj.k] ubZ fnYyh esa fopkjk/khu vks0,0 la0&588@2019 ds lEcU/k esa fnuakd 09-12-2019 dks ftykf/kdkjh egksn;] eFkqjk] uxj vk;qDr] egksn;] uxj fuxe] eFkqjk&o`Unkou]

eFkqjk ,oa {ks=h; vf/kdkjh m0iz0 iznw"k.k fu;a=.k cksMZ] eFkqjk }kjk fd;s x;s fujh{k.k ds nkSjku QksVks dk QksVksxzkQA